1	2
कन्नड़	59
कोंकड़ी	2
मलयालम	58
मणिपुरी	7
मराठी	41
नेपाली	1
उड़िया	29
पंजाबी	16
तमिल	65
तेलुगु	64
अवधी	3
भोजपुरी	3
बोड़ो	1
हरियाणवी	2
राजस्थानी	1
तुलु	3

Title clearance of newspapers

6990. SHRI MOHAMMED AFZAL alias MEEM AFZAL: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) the number of applications received by the Registrar of Newspapers during the period from 1-4-94 to 31-3-95 for title clearance of new newspapers;

(b) the number of titles cleared during the said period; and

(c) the number of applications for title clearance pending as on 1-4-95?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI K. P. SINGH DEO): (a) During the period from 1-4-1994 to 31-3.1995, 20581 applications were received by the Registrar of Newspapers for India for title clearance.

(b) 11610 applicatons for titles were cleared. In the case of 8601 applications, titles were not available for clearance.

(c) 370 applications were pending as on 1.4.1995.

समाचार पत्रों की लागत में वृद्धि

6991. **श्री सतीश प्रधान :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) देश में समाचार पत्रों के महंगा होने के क्या कारण हैं तथा इसके लिए कौन उत्तरदायी है।

(ख) क्या अखबारी कागज प्रदान करने की सरकारी नीति इस महंगाई के मूल कारण की जिम्मेदार है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस पर विचार कर रही है तथा उक्त उल्लिखित मूल कारण को दूर करने का प्रयास कर रही है;

(घ) स्वदेशी अखबारी कागज और विदेशी अखबारी कागज की कीमतों में इतना अधिक अन्तर होने के क्या कारण हैं;

(ङ) स्वदेशी कागज के मंहगे होने के क्या कारण हैं जबकि विदेशी कागज अपेक्षाकृत सस्ता है; और

(च) स्वदेशी कागज के घटिया होने के क्या कारण हैं जबकि विदेशी कागज की गुणवत्ता बेहतर है और वह सस्ता है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य-मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) समाचार पत्र उद्योग निजी क्षेत्र में है और यह एक प्रतियोगी बाजार में काम करता है । उनकी कीमतें अलग-अलग प्रबन्धक वर्गों द्वारा निश्चित की जाती हैं ।

(ख) जी, नहीं । समाचरपत्रों को अखबारी कागज की अबाधित आपूर्ति सुनिश्चित करना ही सरकारी नीति का लक्ष्य है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) भारत में समाचारपत्र अपनी स्वयं की प्रतियोगी कीमतें नियत करने के लिए स्वतंत्र हैं । विदेशी समाचार-पत्र अपने बाजारों में प्रचलित बाजार शर्तों के तहत अपनी कीमतें नियत करते हैं ।

(ङ) और (च) वर्तमान में स्वदेशी अखबारी कागज विदेशी अखबारी कागज की अपेक्षा सस्ता है । तथापि, मिलों द्वारा प्रयुक्त निवेश एवं प्रौद्योगिकी के कारण गुणवता में अन्तर है ।

श्रव्य तथा दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा अपनाए गए नीतिगत दिशा-निर्देश

6992. **श्री सतीश प्रधान :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रव्य तथा दृश्य प्रचार निदेशालय (डी०ए०वी०पी०) की विज्ञापन-नीति क्या है;

(ख) सभी समाचार पत्रों के प्रति सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा एक समान नीति न अपनाने के क्या कारण हैं;

(ग) श्रव्य तथा दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा प्रत्येक पंजीकृत समाचार पत्र को विज्ञापन प्रदान न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस भेदभाव के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य-मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) सरकारी विज्ञापनों का मुख्य उद्देश्य समाचारपत्रों तथा पत्रिकाओं के माध्यम से यथासंभव अधिकतम कवरेज प्राप्त करना है । इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए और निधियों की उपलब्धता के अधीन, इस नीति का उद्देश्य संतुलित एवं न्याय संगत विज्ञापन प्रदान करना है ।

(ख) विज्ञापन नीति सभी समाचरपत्रों पर समान रूप से लागू है ।

(ग) भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक के कार्यालय में 38000 से अधिक समाचरपत्र पंजीकृत हैं जबकि वर्तमान में सरकारी विज्ञापन जारी करने हेतु विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय के पैनल में केवल 5322 समाचरपत्र/पत्रिकाएं हैं । विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय के पैनल में सभी समाचरपत्रों/पत्रिकाओं को प्रत्येक वर्ष कम से कम तीन विज्ञापन अनिवार्य रूप से जारी किए जाते हैं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

भारत के समाचार पत्रों का रजिस्ट्रार

6993. **श्री सतीश प्रधान :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार द्वारा समाचार पत्र के लिए नाम प्रदान करते समय समाचार पत्रों पर किस प्रकार नियंत्रण बनाए रखा जाता है;

(ख) यदि खुले बाजार की नीति के कारण कोई व्यक्ति भारत सरकार से अखबारी कागज नहीं खरीदता है तो